

संशोधित अनुमान 2007-2008

वर्ष 2007-2008 के लिए व्यय के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में 28,852 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि दर्शायी गई है। जबकि आयोजना व्यय में 2,424 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शायी है, वहीं आयोजना-भिन्न व्यय में 26,428 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। जिन प्रमुख मदों में घट-बढ़ हुई, है उन्हें नीचे दर्शाया गया है :-

			(करोड़ रुपए)
बजट	संशोधित	घट-बढ़	
2007-08	2007-08	बचत(-)/ आवध्य(+)	

आयोजना-भिन्न

1. व्याज संदाय और ऋण शोधन	158995	171971	(+)	12976
2. रक्षा व्यय	96000	92500	(-)	3500
3. खाद्य सब्सिडी	25696	31546	(+)	5850
4. उर्वरकों पर सब्सिडी	22451	30501	(+)	8050
5. व्याज सब्सिडी	2276	2658	(+)	382
6. पेंशन	23488	24193	(+)	705
7. सामरिक महत्व की लाइनों के प्रचालन हेतु रेलवे को लाभांश राहत/ क्षतियों की प्रतिपूर्ति	1597	2162	(+)	565
8. शिक्षा	3634	4079	(+)	445
9. पूंजी परिव्यय	49314	49635	(+)	321
10. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	91970	92604	(+)	634
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	475421	501849	(+)	26428
आयोजना				
1. केन्द्रीय आयोजना	154939	148669	(-)	6270
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	50161	58855	(+)	8694
जोड़ (आयोजना) व्यय	205100	207524	(+)	2424

आयोजना-भिन्न

- यह वृद्धि मुख्यतया बाजार स्थिरीकरण योजना, बाजार ऋणों पर व्याज की अधिक अदायगी और क्षतिपूर्ति व अन्य बांडों के कारण है।
- न्यूनतर पूंजीगत व्यय के कारण।
- यह वृद्धि मुख्यतया न्यूनतम समर्थन मूल्य, रखाव लागत, आदि के कारण है।
- यह मुख्यतया घरेलू उर्वरकों की निविष्टि लागत और आयातित उर्वरकों की लागत में वृद्धि के कारण है।
- मुख्यतया निर्यात संवर्धन के अंतर्गत व्याज सब्सिडी और नाबार्ड के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को व्याज सहायता के कारण है।
- मुख्यतया अतिरिक्त मंहगाई राहत के प्रभाव के कारण
- सामरिक महत्व की लाइनों के प्रचालन पर रेलवे को हानियों की प्रतिपूर्ति पर बकाया के भुगतान के कारण।
- सभी पात्र विश्व विद्यालयों, मानव विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदानों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता।
- यह वृद्धि मुख्यतया सामाजिक और अवसंरचना विकास के लिए पहलों के निधियन और एसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक के पण्य की अर्जन लागत में कमी हेतु एकमुश्त प्रावधान के निवल प्रभाव के कारण है।

आयोजना

- समग्र तौर पर यह कटौती कृषि,, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम और रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता और रेलवे में बढ़ोतरी का निवल प्रभाव तथा परमाणु ऊर्जा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा तथा विद्युत के तहत की गयी कमी के कारण है।
- यह बढ़ोतरी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, अन्य परियोजनाओं, त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की वजह से है।